अपनी रांची (झारखंड रांची) विशेष रांची (रविवार), 16 नवंबर, 2014 8

आदिम जनजाति बिरहोर वंचित है सरकारी योजनाओं से

आलोका

झारखंड के बिरहोर आदिमजनजाति समूदाय के पास अपने लिए अनेकों समस्या आज भी मौजूद है. मुख्य गांव से दूर कही उनका निवास कभी पत्तों के कुब्बा में रहने वाले अपने समूदाय के साथ आज भी जीवन बचाने के लिए जूझ रहा है. मुख्य गांव की आबादी से कम ज्ञान और जानकारी आभाव शिक्षा का अस्त शुन्य के बराबर उसे जानकारी देने वाला कोई नहीं ऐसे स्थिति में अपने में जुझता हुआ अपनी समझदारी विकसित कर रहे है. तक्नीकी विकास के युग में मानव जहां साइबर की दुनिया के साथ जूडकर अपनी आशाओं की पूर्ति करता है. वही बिरहोर आदिमजनजाति समुदाय इस दुनिया के अंतिम पायदान पर अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहे है. इन समुदाय को विकास की समझदारी विकसित नहीं हो पाई है आज भी वो अपने छोटे समूह और छोटी आबादी के बीच जीवन यापन के लिए बाध्य है. देश और राज्य में आदिवासी सब प्लान के अन्तर्गत बजट है. इस बजट का उपयोग मानव विकास के इस अंतिम समुदाय बिरहोर समूदाय को क्यों विकसित नहीं हो पाया, यह चिंता का विषय है. सोचने की जरूरत है कि मानव का विकास जहां से होता है मानव जिसने कभी कंद मूल खा कर आपने को बचाया बढ़ाया और एक समाज बनाया वह समाज अपने पूर्वज को नकारता है यह अधिकार सिर्फ सरकारी व्यवस्था को नहीं जाता बल्कि सामाज में रहने वाले उन तामाम लोगो की ओर इंगित करता है कि यह वह समाज है जहां एक ओर तक्नीकी विकास की आवाज गुंज रही है वहीं बिरहोर समाज अपने जीवन की बाटजोह रहा है. यह समाज जहां हम सभी रहते है वही समाज के वन क्षेत्र में यह आदिमजनजाति समुदाय बिरहोर का भी समाज है. यह समाज अन्य समाज से काफी भिन्न है. पूरी दुनिया मंगल में जाने की चर्चा कर रहा है, वही बिरहोर समुदाय के पास भूख, गरीबी, बेरोजगारी, आवास की समस्या, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे समस्या बरकरार है. यही नहीं आजादी के 67 सालों के बाद बिरहोर समूदाय मूख्यधारा से जुड नहीं पाया. जबकि इसके लिए सरकार के पास आदिवासी कल्याण विभाग के नामक एक विभाग है जिसके अन्तर्गत वंचित समूह को विकास के लिए लाखों योजना और बजट मौजूद है फिर भी ये विकास से वंचित है.

घट रहे है बिरहोर की संख्या

आबादी के हिसाब से सबसे छोटी आबादी, योजना को गौर करे तो योजनाएं बिरहोर के गांव के पहुंच से बाहर, उनकी दशा देखे तो आदिम युग के सदी के द्वार पर खड़ा उनका जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बिरहोर की पकड़ नहीं के बराबर है वन भूमि ही इनका निवास स्थान, वन ही जीविका का आधार, पर उस पर मालिकाना हक नहीं. 60 साल पहले बिरहोर समूदाय को घूमकड़ के रूप में जाना जाता रहा है उसने अपना एक स्थान को निवास का जगह नहीं बनाया बल्कि छोटे-छोटे समूह घुम-घुम कर निवास किये. उनके घुमने के वजह उनके खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ था. 60 साल पहले वनें घने थे जिस पर उनकी निर्भरता थी, धीरे-धीरे वनों की स्थिति खराब होने लगी बिरहोर समूदाय की जीविका पर संकट बढ़ते गया वह उस स्थान को छोड कर दुसरे जंगल या गांव के निकट निवास करने लगे. अब यह स्थिति 60 साल वाली नहीं है. अब बिरहोर समूदाय स्थाई रूप से निवास करने लगे है. जंगल से खाद्य- सामग्री पर निर्भरता कम हुए है अब अनाज को खाना सीख गये है. अब सरकार की ओर से दो महिना पर 70 किलो चावल मिला है. इसके अलावे बिरसा आवास जो सब के पास नहीं है. 60 साल वाला बिरहोर की स्थिति में परिवर्तन आया है उस वक्त लोग पूरी तरीके से जंगल पर निर्भर होते थे और अन्य समूदाय के साथ उनका मिलना जूलना नहीं होता था. अब वह स्थिति नहीं रही बिरहोर समूदाय के जीवन परिवर्तन के साथ अपने परिवार के साथ काम की खोज में जाते है. रोजी रोजगार की तलाश में घूमते है. यानि की वे अपने को जीवत रखने के लिए आत्म निर्भर होना चाहते है इसके लिए काम की तलाश में है. काम उन्हें मिले इसके लिए वे पलायन कर दुसरे जगह जाते है जहां उसे भोजन मिल सके.

ब्रिहार एकीकृत राज्य में जनजातिय कल्याण शोध संस्थान द्वारा किये गये काम से पता चलता है कि एकीकृत बिहार के समय 11 जिले दक्षिण बिहार के इलाके हुआ करता था जहां बिरहोर समुदाय की अच्छी खासी आबादी थी. विगत सौ वर्षो द्वारा किये गये संकलन एवं विभिन्न जनगणना प्रतिवेदनों पर आकल करने पर बिरहोर समूदाय के जनसंख्या में प्रर्याप्त वृद्वि हुई है बिरहोर की जनसंख्या 1871 से 1981 तक इनकी जनसंख्या 4377 हो गयी थी. जिसमें 11 जिलों के 50 प्रखंडों एवं लगभग 75 गांव में वे निवास करते थे. 1991 सेंसक्स में बिरोहर की आबादी 8038 देखा जाए तो उनके ग्रोथ रेट 45.54 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. लेकिन 2001 के सेंसक्स में बिरहोर की आबादी घट कर 7514 हो गयी. इसके घटने का सरकारी कारण मात्र एक है कि वे घुमकर है, और कही चले गये होगे.

सरकारी योजना और बिरहोर का गांव

यूएनडीपी के फेलोशिप के तहत लिखने के काम करने के क्रम में बिरहोर समूदाय के कई पहलू को जानने और समझने का मौका मिला. सबसे पहले विभिन्न योजनों के साथ जूड़ कर काम करने वाले समूह संगठन इंटरनेट आदि से जानकारी प्राप्त हुई. भारत एक कल्याणकारी राज्य है इसके अन्तर्गत देश में सबसे अंतिम समूदाय जिसे वास्तव में सहयोग या सरकार की सहायता की जरूरत है उसके लिए अनेकों योजना बनाई, यह योजना 60 के दशक में ही बन गयी थी, बीच-बीच में जरूरत के हिसाब से उसमें परिवर्तन कर कई नयी योजनाओं को जोड़ा गया जिसमें एक्लब्य मोर्डल/आवासीय आश्रम विद्यालय, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रावृति, साइकिल वितरण, कॉमशियल पाइलॉट टेनिंग प्रोग्राम, अबेडकर छात्रवृति, बिरसा मुंडा तक्नीकी छात्रवृति बिरसा मुंडा आवास योजना जनश्री इंशोरेंश योजना शामिल है. इन योजनाओं की खोज करनी शुरू किये तो पता चला कि बिरहोर समूदाय सरकार की योजनाओं पर अभी टीके हुए नहीं है सरकार की योजना बिरहोर समुदाय तक पहुंच नहीं पाती कारण की सरकार के कार्यालय और बिरहोर के गांव की दूरी लम्बी है और सरकारी योजनाओं को लागू कराने के दूरी भी उससे कही ज्यादा लम्बी है. सरकारी योजनाओं की जानकारी उन्हें नही है. झारखंड में बिरहोर का निवास मुलतः रांची, गुमला, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़ लोहरदगा गिरिडीह में इनकी आबादी अधिक है और स्थाई रूप से निवास कर रहे इनके लिए बिरसा आवास योजना के तहत घर का निर्माण किया गया है किन्तु नये परिवार अभी भी इस योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किये गये है. और न शामिल करने की संभावनाएं है. जिनका पास बिरसा आवास है एक घर कमरा वाले घर में बिरहोर खुद तो रहता ही है साथ में बकरी और मुर्गी रखता है और जीवन यापन करता चलाता है. उनका निवास स्थान प्रखंड कार्यालय से 30-35 किमी की दूरी में होते है. अपनी आजीविका के तलाश के लिए उन्हें पैदल ही अपने गांव से बाहर निकलना पड़ता है. इस तक्नीकी युग में संसाधन के आभाव वाला जीवन कोई व्यतित कर रहा है वह है बिरहोर और तमाम आदिजनजाति की यही स्थिति है. जब ब्लॉक कार्यालय में उसे दो महिना पर 70 किलो चावल अन्तोदय योजना के अन्तर्गत मिला है वह भी उसके लिए बोझ बन जाता है ब्लॉक कार्यालय से अपने निवास आनाज लाने में 50 से 100 रूप्या खर्च हो जाता है उनके पास साइकिल तक नहीं है जबकि सरकारी योजना साइकिल वितरण का प्रावधान है जो उन्हे मिलता नहीं और बिरहोर जानते नहीं की सरकार से हमें क्या मिलना है, इस चावल को लाने के लिए 50 से 100 रूपये कमाने के लिए उसे दुसरे के यहां काम करना पड़ता है. वह भी वो जमा नहीं कर पाते कुछ बिरहोर समुदाय चावल अपने घर नहीं ला पाते ऐसे स्थिति में वे पास के बाजार में चावल को बेच देते है. चावल बिरहोर समूदाय के लिए एकमात्र जीविका का सहारा है जिसे सरकार की ओर से मिलता है.

खाद्य सुरक्षा का सवाल

मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कार्बनहाइड्रेट के अलावा प्रोटिन, बसा, विटामिन की जरूरत है. यह उसे नियमित नहीं मिल पाता है. जिससे अधिकांश पर मानसिक और शारीरिक विकास पर दुष्प्रभाव या विकास नहीं हो पाता है. प्रदूषित होते जंगल और कम होते वनभूमि के कारण बिरहोर समूदाय के पास खाद्य सुरक्षा का सवाल बड़ा सवाल बन गया है जिस कारण उनकी आबादी कम होती जा रही है. अब तक अधिकांश बिरहोर समूदाय को वन भूमि में पट्टा देना था वह काम सरकार की ओर से नहीं हुआ है. अधिकांश बिरहोर कृषि करना नहीं जानते है. आज भी वे गैठा वन से खोज कर खाते है वह उनके प्रिय खाद्य सामग्री है. वे धान उत्पादन करना नहीं जानते है. लेकिन अब गांव से बाहर निकल कर श्रम करते है जिससे वह अपने परिवार के लिए साग-सब्जी की जूगाड़ कर सके. वे शारीरिक श्रम अधिक करते है बदले में उन्हे अच्छे भोजन नही मिल पाती है. सरकार के पास खाद्य सुरक्षा कानून होते के बावजूद बिरहोर समुदाय को भूख से मौत जैसी घटना होती है. खाद्य सुरक्षा पर काम करने वाले बलराम उच्चतम न्यायालय के एडवाइजर ने बताया कि अभी भी बिरहोर समुदाय के नये परिवार को चिन्हत नहीं किया है गांव में नहीं मिला है कई जगह पर ब्लॉक ऑफिस में मिलना है जिसके लाने के लिए खर्च पड़ता बिरहोर समूदाय उसे उठा नहीं पाते है. साथ ही न्यूटिशन भोजन का अभाव उनके विकास को रोकता है. उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि सभी आदिमजनजाति को अन्तोदय योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत लाभ पहुंचाना है जो नहीं हो पा रहा है. सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश का उलुघंन कर रही है. बिरहोर समूदाय के साथ भेद भाव होता है. कोई भी योजना चलती है वह मुख्य गांव में आते है जागरूक गांव के लोग भी उसे अपने में शामिल नहीं करते है. बिरहोर के लिए शिक्षा और रोजगार सबसे बड़ी समस्या है मनेरगा के काम में उन्हे जोड़ा नहीं गया है सरकार बिरहोर के साथ भेदभाव करती है.

ग्लोबल स्वरूप ले चुका बिरोहर का गांव

गुमला जिला के विशुनपूर से 4 किलो मीटर अंदर बिरहोर का एक टोला पगडंडी से हो कर जहनगुटूआ में बसा है आदिमजनजाति बिरहोर के एक्लवता टोला जिसमें 35 से 40 घर, आदिमजनजाति बिरहोर ने कड़ी मेहनत से बदल दिया अपनी बिरहोर टोली का जीवन 1955 में समय से ये आदिमजनजाति गुमला के जहनगूटूआ पंचायत हेलता बिशूनपूर के 5 किमी अंदर के गांव में निवास करते किये. उस वक्त वन छोड़कर उनके पास जीविका का कोई आधार नहीं था. वन घना और वन जीव के संख्या वन के अंदर अधिक थी. लोग शिकार मारने के कला से प्रंगत थे वन से फल फूल तोड़ कर अपनी आजीविका चलाते थे. घर गुगू पतों से बना कर रहते है अपनी तमाम परम्परागत व्यवस्था के साथ अपने समूदाय के साथ जीवन यापन करते थे. वन माफियाओं का वन में लकड़ी का दोहन तेजी से होने लगा वन कटने लगे और वन कम पड़ने लगे ऐसे स्थिति में

उनके पास जीविका का संकट उत्पन्न हो गया लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया. स्थिति यहां तक आ पहुंची की आदिमजनजाति बिरहोर के भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो गयी. अपने समय के संघर्ष के साथ कड़ी मेहनत से बिरहोर समूदाय ने अपने जीवन में बदलना शुरू किया. 1981- 82 आते-आते बिरहोर समूदाय वन से निर्भरता समाप्त कर दी और श्रम कि निर्भरता की ओर बढ़ते चले गये. अपने पूर्वजों के बल पर अपने गांव को सजाना सवारना शुरू की दिया. विकास भारती ने बिरहोर समूदाय से सम्पर्क कर उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार से गुहार लगाई और सरकारी योजना बिरसा आवास से उनकी मुलाकात हुई बिरहोर अब वो पत्ते वाले घर में नहीं रहते है उनका घर मिट्टी का बन चुका है वे छोटी छोटी जमीन पर धान का उत्पाद के साथ जानवर रखने लगे है. युवा वर्ग मजदूरी करता है. महिलाए घर में रस्सी बनाने के काम करती है बुर्जुग मवेशी चराने जंगल में जाते हैं अपने गांव में, खाने वाले पेड़ पौधो के बारे में जानकारी हासिल कर उन्हे अपने हित के लिए प्रयोग करना शुरू किया. गांव की दशा सुधरी और गांव के बाहर लोगो का सम्पर्क हुआ. बिरहोर समूदाय अब अपने लिए सरकारी योजनाओं का लाभ के लिए ब्लॉक कार्यालय जाते है. गांव में मिट्टी का घर और मवेशी और छोटी खेत के अलावा श्रम बेचना, रस्सी बना कर बाजार में बेचना उनका पेशा हो गया है.

जेहनगुटूआ में जाने के क्रम पर पता चला कि बिरहोर समूदाय के पास घर के अलावा उनके जीने खाने के लिए उनकी जरूरत की सभी कुछ है पर उस पर मालिकाना हक नहीं है कुछ लोगो को सरकार की ओर से वन भूमि पर पट्टा दिया गया है नये परिवार को नजरअंदाज किये हुए है बिरहोरों की बढ़ती आबादी को देखते हुए एक आंगनबाडी की स्थापना कर दिये गये है जिसमें बिरहोर समुदाय की एक महिला वहां बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है जिसमें 40 बच्चे है बच्चे उस आंगनबाडी को खीचडी स्कूल बोलते है. गांव में सर्वशिक्षा अभियान के तहत 5वां कलास तक के बच्चें के लिए स्कूल की व्यवस्था करनी है वह नहीं हो पाया है 1 किमी की दूरी में आदिमजनजाति के आवासीय विद्यालय है जिसकी स्थिति र्जजर है. बिरहोर अपने श्रम बेच कर अपने बच्चों को शिक्षा के लिए 4 से 6 किमी पैदल पढ़ाने भेजते है. जिससे गांव में संजय बिरहोर एक साल पहले सीआरपीएफ में गया है अभी चन्नय में है. गांव का रोलमॉडल है गांव का पहला लड़का को अपने मेहनत के बल पर सरकार ने नौकरी दिया हैं जबकि 2008 में राज्य सरकार ने आदिमजनजाति समुदाय के शिक्षित लोगो को सीधे नियुक्ति का प्रवधान किया गया था जिससे गुमला को डीसी ने पूरा आज तक नहीं कर पाये है. बिरहोर कॉलनी में बलदिना बिरहोर बीए फाइनल की छात्रा है और मरकिन बिरहोर इंटर तक पढ़ चुकी है सलेम बिरहोर मैट्रिक कर के घर में है. इनको नौकरी नहीं मिली है. गांव के विजय बिरहोर ने बताया कि सरकार के दो लोग डीसी और डीडीसी बिरहोर का विकास नहीं चाहते है वे चाहते तो गांव शिक्षित युवाओं को नौकरी मिलती. यहां की डीसी ने पूरे गुमला में एक भी बिरहोर को सरकारी नौकरी नहीं दिया है. लम्बे समय से 32 किलो चावल और 4 लीटर मिट्टी तेल दे रही है परिवार बढ़ रहा है वन भूमि पर पट्टा नही दिया. हमारे पास परिवार चलाने के लिए श्रम बेचने के अलावा कोई दुसरा कोई विकल्प नहीं है चावल लाने के लिए हमें खुद भाड़ा लग जाता है. वनभूमि में दावा पत्र भरने के लिए ब्लॉक कार्यालय जाना पड़ता है उसके लिए भी खर्च करना पड़ता है एक दिन में सरकार काम नहीं करती है. और सरकार वन भूमि दे भी देगी तो सिचाई के लिए पानी कहां से लाएगें. बिरहोर कॉलनी में स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है. स्वास्थ्य समस्या आने पर खुद से इलाज के लिए बाहर निकल कर इलाज कराते है. ....

जारी

अपनी रांची (झारखंड रांची) विशेष रांची (रविवार), 30 नवंबर, 2014 8

..आदिम जनजाति बिरहोर वंचित हैं सरकारी योजनाओं से

आलोका

झारखंड के बिरहोर आदिमजनजाति समुदाय के पास अपने लिए अनेकों समस्या आज भी मौजूद है. मुख्य गांव से दूर कही उनका निवास कभी पत्तों के कुब्बा में रहने वाले अपने समुदाय के साथ आज भी जीवन बचाने के लिए जूझ रहा है. मुख्य गांव की आबादी से कम ज्ञान और जानकारी आभाव शिक्षा का अस्त शून्य के बराबर उसे जानकारी देने वाला कोई नहीं ऐसे स्थिति में अपने में जुझता हुआ अपनी समझदारी विकसित कर रहे है. तकनीकी विकास के युग में मानव जहा साइबर की दुनिया के साथ जुड़कर अपनी आशाओं की पूर्ति करता है. वही बिरहोर आदिमजनजाति समुदाय इस दुनिया के अंतिम पायदान पर अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहे है. इन समुदाय को विकास की समझदारी विकसित नहीं हो पाई है आज भी वो अपने छोटे समूह और छोटी आबादी के बीच जीवन यापन के लिए बाध्य है. देश और राज्य में आदिवासी सब प्लान के अन्तर्गत बजट है. इस बजट का उपयोग मानव विकास के इस अंतिम समुदाय बिरहोर समुदाय को क्यों विकसित नहीं हो पाया, यह चिंता का विषय है. सोचने की जरूरत है कि मानव का विकास जहा से होता है मानव जिसने कभी कंद मूल खा कर आपने को बचाया बढ़ाया और एक समाज बनाया वह समाज अपने पूर्वज को नकारता है यह अधिकार सिर्फ सरकारी व्यवस्था को नहीं जाता बल्कि सामाज में रहने वाले उन तामाम लोगो की ओर

इंगित करता है कि यह वह समाज है जहां एक ओर तकनीकी विकास की आवाज गुंज रही है वहीं बिरहोर समाज अपने जीवन की बाटजोह रहा है. यह समाज जहां हम सभी रहते है वही समाज के वन क्षेत्र में यह आदिमजनजाति समुदाय बिरहोर का भी समाज है. यह समाज अन्य समाज से काफी भिन्न है. पूरी दुनिया मंगल में जाने की चर्चा कर रहा है, वही बिरहोर समुदाय के पास भूख, गरीबी, बेरोजगारी, आवास की समस्या, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे समस्या बरकारार है. यही नहीं आजादी के 67 सालों के बाद बिरहोर समुदाय मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाया. जबकि इसके लिए सरकार के पास आदिवासी कल्याण विभाग के नामक एक विभाग है जिसके अन्तर्गत वंचित समूह को विकास के लिए लाखों योजना और बजट मौजूद है फिर भी वे विकास से वंचित है.

घट रहे है बिरहोर की संख्या

आबादी के हिसाब से सबसे छोटी आबादी, योजना को गौर करे तो योजनाएं बिरहोर के गांव के पहुंच से बाहर, उनकी दशा देखे तो आदिम युग के सदी के द्वार पर खड़ा उनका जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बिरहोर की पकड़ नहीं के बराबर है वन भूमि ही इनका निवास स्थान, वन ही जीविका का आधार, पर उस पर मालिकाना हक नहीं. 60 साल पहले बिरहोर समुदाय को घुमक्कड़ के रूप में जाना जाता रहा है उसने अपना एक स्थान को निवास का जगह नहीं बनाया बल्कि छोटे-छोटे समूह घुम-घुम कर निवास किये. उनके घुमने के वजह उनके खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ था. 60 साल पहले वनें घने थे जिस पर उनकी निर्भरता थी, धीरे-धीरे वनों की स्थिति खराब होने लगी बिरहोर समुदाय की जीविका पर संकट बढ़ते गया वह उस स्थान को छोड कर दुसरे जंगल या गांव के निकट निवास करने लगे. अब यह स्थिति 60 साल वाली नहीं है. अब बिरहोर समुदाय स्थाई रूप से निवास करने लगे है. जंगल से खाद्य- सामग्री पर निर्भरता कम हुए है अब अनाज को खाना सीख गये है. अब सरकार की ओर से दो महिना पर 70 किलो चावल मिला है. इसके अलावे बिरसा आवास जो सब के पास नहीं है. 60 साल वाला बिरहोर की स्थिति में परिवर्तन आया है उस वक्त लोग पूरी तरीके से जंगल पर निर्भर होते थे और अन्य समुदाय के साथ उनका मिलना जूलना नहीं होता था.

अब वह स्थिति नहीं रही बिरहोर समुदाय के जीवन परिवर्तन के साथ अपने परिवार के साथ काम की खोज में जाते है. रोजी रोजगार की तलाश में घूमते है. यानि की वे अपने को जीवत रखने के लिए आत्म निर्भर होना चाहते है इसके लिए काम की तलाश मे है. काम उन्हें मिले इसके लिए वे पलायन कर दुसरे जगह जाते है जहां उसे भोजन मिल सके. बिहार एकीकृत राज्य में जनजातिय कल्याण शोध संस्थान द्वारा किये गये काम से पता चलता है कि एकीकृत बिहार के समय 1.1 जिले दक्षिण बिहार के इलाके हुआ करता था जहां बिरहोर समुदाय की अच्छी खासी आबादी थी. विगत सौ वर्षों द्वारा किये गये संकलन एवं विभिन्न जनगणना प्रतिवेदनों पर आकल करने पर बिरहोर समुदाय के जनसंख्या में प्रर्याप्त वृद्धि हुई है. ..... जारी

अपनी रांची (झारखंड रांची) समाचार रांची (रविवार), 07 दिसंबर, 2014 7

..आदिम जनजाति बिरहोर वंचित हैं सरकारी योजनाओं से

आलोका

जितेन्द्र पाहन बिरहोर टोली सामाजिक काम के साथ जुड़े है उन्होंने बताया कि बिरहोर के नाम पर कई योजना चलती है सरकार के उदासीन रवैया के कारण इसका लाभ बिरहोर समुदाय नहीं उठा पा रहे. बिरहोर के पास भोजन का संकट है वे दिन भर मेहनत मजदूरी कर जीवन चला रहे है. आदमी का एक मात्र जरूरत चावल नहीं एक आदमी के जीवन में कई जरूरत है जिसकी पूर्ति का एक छोटा सा भाग भी सरकार पूरा करती तो बिरहोर को दिशा मिलता, पर सरकार ने कभी चाहा ही नहीं. बिरसा आवास बिरहोर की जरूरत है तो समस्या भी- आदिम जनजाति के बिरहोर समुदाय को बिरसा आवास मिला. जिनका आवास पक्का का है उसके लिए समस्या बन गया है आवास में टूट फूट हो जाए तो उनके पास सिमेंट बालू लाने के लिए पैसा नही है वे किसी तरह मिट्टी से उसे मरम्मत करते है. बरिश और ठंड में समस्या हो जाती है ऐसी स्थिति में खपड़ा और मिट्टी के बने घर ज्यादा उपयोगी है. सरकार इन दिनों टीन के चदरा के सीट छत पर डाल रही है जिससे गरमी के दिनों में गरमी अधिक लगता है. बारिश के दिनों में आवाज अधिक आते है और ठंड के दिनों में ठंड अधिक लगते है. बिरहोर के घर बनता जरूर है पर उसका समय-समय पर मैनटेनेंस नहीं होता है. जिससे कई बिरहोर के घर टूट-फूट गया है. बनाने का प्रावधान नहीं है. बिरहोर महिला की स्थिति सबसे दयनीय मंजू बिरहोर, मंजू बिरोहर, सरस्वती बिरहोर, रीमा बिरहोर, से करीब 2 घंटे तक बातचीत के क्रम में उसने अपने समुदाय की औरतों की स्थिति के बारे में बताया कि हम अपने समुदाय में रहते है हमने बाहर की दुनिया नहीं देखी है हमारे पास पूरे दिन और आधी रात का काम होता है. अपने घर के बच्चों के लालन पालन के अलावा जंगल से वन उत्पादन को लाकर घर में जमा करते है. घर के लिए खाना बनाना घर की सफाई पति का देख भाल के अलावा घर का खर्च चलाने के लिए औरते रस्सी बना का

परिवार को सहयोग करती है. औरतें दिन के खाली समय में सिमेंट के बोरा का जमा कर उससे रस्सी बनाने का काम करते है जिसे साप्ताहिक हाट में बेच कर दिनभर में 70 से 80 रूपये कमाते है इससे कभी कभी साग सब्जी के अलावा बच्चों के कपडे दवा और कुछ अन्य जरूरी समान खरीदते है. चुनाव नहीं जानती है पर मंजू बिरोहर सरस्वती बिरहोर रीमा बिरहोर और गांव की सभी महिलाएं चुनाव आने पर वोट डालने सभी जाती है पर उन्हें नहीं पता कि सरकार क्या होती है सरकार का का मतलब वे ब्लॉक कार्यालय ही जानते है. प्रधानमंत्री कौन है झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री कौन है. इनका कहना है हम पढ़े नहीं है इसलिए जानते नहीं है शायद राजनीतिज्ञ को जानने के पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है. इन लोगो ने कहा चुनाव के समय आने से गांव में चर्चा होती है और स्कूल में जाकर वोट डालते है पर मेरे वोट से क्या होता नहीं जानती है. इन महिलाओं की बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं इनकी दुनिया जंगल और घर है इसके अलावे अपने मां के घर जाते है मां के घर से वापस अपने पति के घर आती है. ये लोगो नहीं जानते है रांची कहा है. गांव में रांची की चर्चा होती है पर वह कहा है नहीं पता औरतों के अधिकार के बारे में कोई जानकारी नहीं. गांव से बाहर निकलती नहीं. गांव के ग्राम सभा होती है वहा जाते है पर कुछ नहीं बोलती है. उनका मानना है ग्राम सभा हमारी बातों को नहीं सुनेगी. युवाओं के बल पर टीका है बिरहोर का जीवन- 10 से 12 युवाओं का एक समूह जेहनगुटूआ में है ये युवाओं के कम शिक्षित है कॉलेज की दूरिया और आर्थिक तंगी ने उसे हाई स्कूल और कॉलेज का मूह नहीं देखा. घर में खाने की समस्या है जिसकी पूर्ति के लिए वे अपने श्रम को बेच कर. परिवार चलाने में मदद करते है. श्रम की सारी शक्ति युवाओं के ऊपर है. युवाओं ने गांव के लिए श्रम कर उन्हें टेक्टर चलाने का काम सीख लिया है. दूसरे के खेतों में हल चलाने का काम सिख लिया है वे दिन भर गांव से बाहर ट्रेक्टर चलाकर पैसा कमाते है. जहेनगुटूआ में 8 से 10 युवा है, जो इस तरह के काम में जुटे हुए है. प्रति दिन टेक्टर चलाने का काम करते है उन्हीने यह काम इस लिए चुना की इसमें लोगो से सम्पर्क के साथ तकनीकी ज्ञान हो सकेगा साथ में अपने लिए रोजगार के साधन है. आंगनबाड़ी के 40 बच्चे का भविष्य अंधार में

जेहनगुटूआ में सरकार ने आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना कर दी है. जहां बिरहोर के 40 बच्चे आते है. ये बच्चें 3 साल बाद क्या करेंगे इनके माता पिता को नहीं पता है गांव से सरकारी स्कूल की दूरी 4 किमी है. बच्चे को सरकारी स्कूल में पढाने के लिए प्रतिदिन 5 रू भाड़ा खर्च करना पड़ेगा यह 5 रूपये कहा से आएगे. यह सवाल विजय बिरहोर के दिमाग और मन में है. अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते है सजय बिरहोर के 3 बच्चे है इनको स्कूल में पढ़ाने की इच्छा पर 4 किमी की दूरी बच्चे तय नही कर पायेंगे वहा बच्चे को पहुचाना पड़ेगा जिसके लिए हमारे पास साधन नहीं है. आने वाला पीढ़ी भी शिक्षा से वंचित ही रहेगा. संजय बिरहोर बताते है हम जब तक आर्थिक रूप से सक्षम नही होगे अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाएगे.

बेमोल ज्ञान

झारखंड में आदिमजनजाति बिरहोर के परम्परागत ज्ञान और कला रस्सी बनाना रहा है. जंगल के कटने से उनके परम्परागत ज्ञान और कला पर असर हुआ है पहले जंगल से वन उत्पादन और पेड के छाल लाकर रस्सी बनाते थे. अभी भी रस्सियों के लिए बिरहोर प्रसिद्ध रहे है. पहले सालों भर महिला पुरूष मिल कर रस्सी बनाने का काम करती थी. जंगलों से अनेकों प्रकार के छोप लाकर घर में पुरूष एवं महिलाएं दिन भर रस्सी बनाती थी और पुरूष उसे धुम-धुम कर बेचते थे. उनकी रस्सी आसपास के गांव के किसान आने बेल बाधने, पानी भरने के अलावा कई प्रकार के काम में उपयोग करते थे. उस वक्तरस्सी बनाने के जो स्रोत थे वह जंगलों के उदाल, सबई, माहलन, गुंगुपता, तोम्बा, बेंदी तलेत, कुम्भही तथा खेती से सन,ढैचा इत्यादि रस्सी का छोप प्राप्त का तरह-तरह की रस्सियों एवं उपकरणों का निर्माण करते है.

रस्सी का मूल्य इस प्रकार है-

रस्सी से बने सामग्री का नाम	मूल्य
सिक्का	2 5
रू0 से 60 रू0 तक	
लाइड बरहा	6 0
रू0	
डोरी	4 रू0
संगा जोती	1 2
रू0 प्रति जोड़ा	
पगहा	6 रू0
पइनरा जोरी	6 रू0
छोटी डोरी	2 रू0
खाटी रस्सी	8 रू0

से 10 रू0 प्रतिकिलो

स्रोत जनजातीय कल्याण शोध संस्थान

वह समय था जब बिरहोर किसानों की जरूरत के लिए रस्सी बनाकर किसानों को सहायता करते थे. उस वक्त बाजारों में रस्सी की दूकान होती थी बिरोहर कतार में बैठ कर रस्सी बेचते थे. रस्सी के लिए अलग बाजार हुआ करता था. 60 साल बाद वह स्थिति बिरहोर के पास नहीं रही. उनके रस्सी बनाने की कला तो जीवत है पर वह बदल गया. जंगल का स्वरूप बदल गया रस्सी बनाने सामग्री बदल गयी किसान की जरूरत बदल गये बिरहोर और किसान की जरूरत पर फंक आ गया. किसान अब ट्रेक्टर से खेती करने लगे आधुनिक सामान गांव में प्रवेश कर गया. गांव जहां लेन देन की प्रथा थी वह बदल कर सीधे खरीद-बिक्री पर नियंत्रित हो गया. देशी हूनर नकार दिये जाने लगे. जहां कभी पेड़ के छाल की रस्सी बनती थी. वहा अब सीमेंट के बोरे की रस्सी बन रही. बिरहोर ने रस्सी बनाने के काम को जीवित तो रखा पर उसके बनने की चीजे बदल गयी. अब वह बाजार उनके पास नहीं अब गांव की जरूरत उनके कला को नहीं है गांव में अब उनके बनी रस्सी 20 रूपये बिकरही है ऐसी स्थिति में परम्परागत ज्ञान का और परम्परागत जरूरत खत्म होते कगार पर दिखाई दे रहा है. अब बिरहोर सिर्फ रस्सी बनाने के काम में कर रहें है.

झारखंड सरकार के पास कई ऐसे विभाग है जैसे खादी ग्राम उद्योग विभाग, कुटीर उधोग विभाग, और कला विभाग, इन विभागों ने कभी बिरहोर के कला को तवों नहीं दी. वे चाहते तो इन्हें कई अलग- अलग कला की जानकारी दे कर उनके उद्योग को बाजार और दूनिया के स्तर पर रख सकते थे. बिरहोर समुदाय पहले महिला पुरूष दोनों मिलकर रस्सी बनाने का काम करते थे उनके काम के जीवन में परिवर्तन आ गया है वहा अब महिलाएं मात्र रस्सी बनाने का काम करती है.